

त्वरित टिप्पणी : अमेरिका का ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर

इरान और इजरायल की जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने इरान के तीन परमाणु ठिकानों पर देर रात बी 2 बांधर बम से हमला करके भारी तबाही मचाई है। अमेरिका ने इरान और इजरायल युद्ध के लिए बी 2 बांधर, पन्दुज्जी मिसाइलों के जरिए सुनवोजित रूप से इरान पर हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इरान के तीन परमाणु ठिकानों फोरडो, नतांज और इसफहान पर विनाशकारी हमले का दावा करते हुए कहा है, कि यह हमला शांति के लिए किया गया है। अमेरिका के इस जंग में कूदने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से सारी दुनिया में अफरा-तफरी मच गई है। इरान सरकार ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा है, इरान अब चुन-चुन कर अमेरिकी ठिकानों पर सीधे हमले करेगा। अमेरिकी हमले के बाद इरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से भारी बमबारी शुरू कर दी है। इरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े, तथा फ्रांस के जहाजों को निशाने पर ले लिया है। इन पर कभी भी इरान का भारी हमला हो सकता है। इरान इस समय हूं एंड डाई की आक्रामक मुद्रा में है। इरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अपने तीन उत्तराधिकारी घोषित करके अपने तेवर बता दिए हैं। उनके आक्रामक तेवर देखकर पता चलता है कि इरान इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले कर जाएगा। इरान और इजरायल युद्ध में अमेरिका के कूद जाने के बाद सारे विश्व में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से सारे विश्व में अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं। वह जिस तरह का व्यवहार दुनिया के अन्य देशों के साथ कर रहे हैं। उसके बाद चीन-रूस जैसे शक्तिशाली देश अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे चुके थे। युद्ध में यदि अमेरिका कुदेगा, ऐसी स्थिति में चीन और

रूस खुलकर ईरान के पश्च में खड़े होंगे। सारी दुनिया के देशों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी कर रहे हैं। उसको लेकर दुनिया के देशों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ता चला जा रहा है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है, कि चीन और रूस खुले रूप से ईरान के पश्च में न केवल खड़े होंगे यरन जरूरत पड़ने पर वह ईरान के पश्च में युद्ध के मैदान में खुद भी कूद जाएंगे।

अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया का दादा बनना चाहता है। चीन, रूस समेत कई देशों को अमेरिका की यह दादागिरी बदायत नहीं है। इस कारण तृतीय विश्वयुद्ध जैसी संभावना बनती दिख रही है। ऐसी स्थिति में रूस-चीन और उत्तर कोरिया के ईरान के पश्च में युद्ध के मैदान में उत्तरने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका अपने खुद के मकड़जाल में पूरी तरह से फंस गया है, जिससे निकलने का रास्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रहा है।

अग्रीजों से आजाद होने के बाद भारत लोकतांत्रिक देश तो बन गया, लेकिन ठीक 25 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से थोपी गई इमरजेंसी में लोकतंत्र की धन्जियां उड़ गई थी। 25 जून, 1975 की आधी रात अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इंदिरा ने तानाखाही का ऐसा नमूना पेश किया, जो उस पीढ़ी के लोग अब भी नहीं भूल पाए हैं।

वीते साल 25 जून को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद ओम विरला ने आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें आपातकाल को 'प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संविधान पर हमला' बताया गया। इस कदम के बाद सदन में कांग्रेस संसदों ने विरोध किया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि पांच दशक पुराने इस काले दौर का स्मरण नहीं किया जाना चाहिए। संवोगवश, इंदिरा गांधी के सदस्यों ने एक दिन पूर्व 24 जून को सदस्य के रूप में शपथ लेते समय संविधान की प्रतियां उठाई थीं। ऐसे में अहम मुवाल वह है कि क्या कांग्रेस

तकाल को सही मानती है या वह चाहती है कि लोकतंत्र लोकित करने और संविधान निरादर करने वाले इस लाली भरे कदम का स्मरण किया जाना चाहिए? क्या कांग्रेस चाहती है कि अपकाल पर चर्चा नहीं होनी चाहे। लेकिन आपातकाल के भोगी आम लोगों और लोगों का मानना है कि अतीत मूलों को विस्मृत करने से दोहराए जाने का खतरा बढ़ है।

प्रस्तव में कांग्रेस और उसके आपातकाल की गलती को बर नहीं करते। अगर वह गलती स्वीकार करते तो वह कहने की हिम्मत जुटाते 49 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से वह आपातकाल थोपने और राजिक विरोधियों, मोडिया एवं शिलाफ दमन का चक्र एक भूल थी। कांग्रेस को अपकाल की बाद दिलाना ए आवश्यक है, क्योंकि कुछ समय से वह संविधान तरे में होने का फज्जी हौवा कर उसके प्रति प्रतिबद्धता

नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में भारत अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत की तो किसी को अंदाजा न रहा होगा की यह अभियान जन आनंदोलन का रूप ले लेगा। स्वच्छता आनंदोलन के साथ देखते ही देखते तरह से राजनेता, अभिनेता, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी व आमजन जुड़ गये वह अपने आप में अद्वितीय ही रहा। अभियान पूरे देश में व्यापक असर तो दिखा ही साथ ही लोगों के दिलों-दिमाग में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रति अभिट छाप छोड़ गया। आज भी लोग सार्वजनिक व निजी स्थलों में कचरा फेंकने, गंदगी करने के पहले सौ बार सोचते हैं। कोविड के समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जन साह्योग को मिशाल के रूप में देश ने देखा है। सरकारी मदद इलाज के इतर जिस तरह से एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आए और लाखों लोगों की जान सुरक्षित किए वह प्रधानमंत्री के आह्वान का ही नतीजा रहा है। मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में कई उल्लेखनीय और अप्रत्युत्तर्व कार्य कर भारत को कई झेत्रों में नई ऊँचाई पर पहुंचाया है। शोचालय पी.एम. आवास निर्माण के बाद बड़ी उपलब्धियों में यदि किसी को मिना जाअगा तो वह है आयुष्मान भारत योजना, जिसने 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इस योजना ने 6 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज कराकर उनके वित्तीय संकट से बचाया। देखा जाए तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिये इलाज पर होने वाला खुर्च कमर तोड़ने वाला होता है। गम्भीर बीमारी के समय तो कई ऐसे परिवार रहे जो खुर्च न उठा पाने की स्थिति में मरीज को अपने हाल पर छोड़ देते थे। आयुष्मान भारत योजना ने अब सब कुछ आसान कर दिया है। सामान्य हो वा असामान्य सभी तरह की बीमारियों की चिन्ता आयुष्मान भारत पर छोड़ी जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के बाहर दिल्लिनगरीया का उत्तम कानूनी समाज है। दिल्लिनगरी

आपातकाल विस्मृत न हो

सम्पादकीय...

नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में भारत

अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत की तो किसी को अंदाजा न रहा होगा की यह अभियान जन आनंदोलन का रूप ले लेगा। स्वच्छता आनंदोलन के साथ देखते ही देखते तरह से राजनेता, अभिनेता, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी व आमजन जुड़ गये थह अपने आप में अद्वितीय ही रहा। अभियान पूरे देश में व्यापक असर तो दिखा ही साथ ही लोगों के दिलों-दिमाग में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रति अमिट छाप छोड़ गया। आज भी लोग सार्वजनिक व निजी स्थलों में कचरा फेंकने, गंदगी करने के पहले सौ बार सोचते हैं। कोविड के समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जन सहयोग को मिशाल के रूप में देश ने देखा है। सरकारी मदद इलाज के इतर जिस तरह से एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आए और लाखों लोगों की जान सुरक्षित किए। वह प्रधानमंत्री के आह्वान का ही नतीजा रहा है। मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में कई उल्लेखनीय और अभूतपूर्व कार्य कर भारत को कई क्षेत्रों में नई ऊँचाई पर पहुंचाया है। सीचालय पी.एम. आवास निर्माण के बाद बड़ी उपलब्धियों में यदि किसी को मिना जाअगा तो वह ही आयुष्मान भारत योजना, जिसने 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इस योजना ने 6 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज कराकर उन्हें वित्तीय संकट से बचाया। देखा जाए तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिये इलाज पर होने वाला खुर्च कमर तो इने वाला होता है। गम्भीर बीमारी के समय तो कई ऐसे परिवार रहे जो खुर्च न उठा पाने की स्थिति में मरीज को अपने हाल पर छोड़ देते थे। आयुष्मान भारत योजना ने अब सब कुछ आसान कर दिया है। सामान्य हो या असामान्य सभी तरह की बीमारियों की चिन्ता आयुष्मान भारत पर छोड़ी जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के बाहर लिनिवन नियन्त्रण कर रखा जानिवापी समा जै। लिनिवन

क्या नरसंहार की इबारत लिखने वाले देश तय करेंगे कि परमाणु शस्त्र कौन

इस्लाइल - ईरान के बीच हिंदू आधुनिक बुद्ध ने पूरे विश्व को सत्त्वा व चित्तित कर दिया है। इस्लाइल गत कई वर्षों से ईरान को बुद्ध में खोजने को पूरी क्षेत्रित कर रहा था परन्तु ईरान सीधे बुद्ध में कृदने से बचता आ रहा था। परन्तु यह 13 जून को इस्लाइल ने ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला कर दिया। इस हमले के कुछ ही समय बाद इस्लाइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने एक टी वी प्रसारण में इस हमले को उचित ठहराते हुये ईरान पर परमाणु बम बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और अपनी चिंता दोहराई कि ईरान का परमाणु बम इस्लाइल को नष्ट कर सकता है। इस्लाइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और शीर्ष सेना कमांडर भी मार दिये। इस्लाइल ने 13 जून को ईरान पर हमला उस समय किया जबकि दो दिन बाद ही यानी 15 जून को ईरान और अमरीका के मध्य परमाणु समझौता होने की तरीख तय थी और यह समझौता किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की उम्मीद भी की जा रही थी। परन्तु इस्लाइल ने समझौते के पहले ही हमला कर ईरान को बड़ा शोक दे दिया। इस्लाइली हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी यह कहकर सबको चौंका दिया कि उन्हें इस हमले की पहले से जानकारी थी और इस हमले में कई ईरानी कट्टरपंथी (परमाणु वाताकारी) मारे गए हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अमर कह समझौता नहीं करता, तो और बड़े हमले ज्ञेलने पड़े।

सकते हैं। यहीं नहीं बल्कि ट्रंप ने इस्लाइंग की पीठ अपथपाते हुये इस्लाइंगों हमलों को रशानदार बताया और कहा कि ईरान को परमाणु हथिवार हासिल करने की इच्छा छोड़नी होगी। साथ ही ट्रंप ने अमेरिका के इस्लाइंग का सबसे बड़ा सहयोगी भी बताया। साफ है ईरान पर इस्लाइंग द्वारा धोखे से किये गये इस हमले का अमेरिका भी बराबर का साझोदूर है।

अब जब 2003 के उस दौर को भी बाद कीजिये जब ईराक में सद्यम हुसैन के शासनकाल में तल्कलीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बुश प्रशासन, ने यह दावा किया था कि सद्यम हुसैन के पास गसावतीक, जैविक और संभक्ति परमाणु हथिवार भी हैं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। यह दावा खुफिया जानकारी पर आधारित बताया गया था। इसी 'खुफिया जानकारी' को बहाना बनाकर अमेरिका ने इऑपरेशन इराकी फ्रीडमर के नाम से ईराक पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की और ईराक को तबाह कर के लौटा। वहाँ तक कि स्थानीय अद्वलत का गठन कर सद्यम हुसैन को फ़ासी पर चढ़ा दिया। ईराक में सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ गसावतीक, जैविक और सामुहिक विनाश के हथियार होने की जानकारी गलत साबित हुई। वहाँ ऐसे हथियार होने के क्षेत्र सबूत नहीं मिले। जगजाहिर है कि अमेरिका द्वारा ईराक पर सैन्य कार्रवाई वहाँ के तेल संसाधनों पर नियंत्रण और मछ्य पर्व में अमेरिकी

मरिक प्रभाव छढ़ाने की इच्छा के तहत की गयी। एक की तबाही व सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका ने तर्क भी दिया या कि सद्यम हुसैन का तानाशाही सन इसकी जमता और धेत्रीय स्थिरता के लिए निकारक था।

बहरहाल आज वही अमेरिका जिसने केवल एक ही तब्बह करने की कोशिश नहीं की बल्कि वह अपन पर 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम लगाने का भी मुनहगार है। वह अमेरिका जो कोरिया, अटेमाला, इंडोनेशिया, क्यूबा, कांगो, लाओस, वतनाम, कंबोडिया, ग्रेनेडा, लेबनान, सीरिया, बिश्वा, अफ़्ल साल्वाडोर, निकारागुआ, ईरान (1987) आमा, झारक, कुवैत, सोमालिया, बोस्निया, सूडान, अफगानिस्तान, चोयोस्लाविया जैसे देशों पर हमले करने व वहां की सत्ता को अस्थिर करने का जिम्मेदार, क्या वह अमेरिका तब करेगा कि किस देश को परमाणु शस्त्र रखना चाहिए और किसे नहीं? या फिर अफ़्लिस्तीन की जमीन पर अमेरिका ब्रिटेन की शह पर क्या जगाये बैठा वह अवैध देश इस्राईल जिसपर तामा में लगभग 82, 000 लोगों को मारने व लगभग 10 लाख लोगों को बेघर कर धेत्र में मानवीव संकट लड़ा का आरोप है वह तब करेगा कि परमाणु शस्त्र से रखना चाहिए और किसे नहीं? जो देश स्वयं पूरे शृंग में अस्थिरता पैलाने, धेत्रीय संघर्ष भड़काने,

के व्यवसाय तथा तेल जैसी सम्पदा पर चिन्ह दृष्टि हों। पढ़ोसी देशों में फूट डलवाकर बुद्ध भड़काना जनक व्यवसाय बन चुका हो वह देश कैसे रेरेत कर सकते हैं कि परमाणु शस्त्र किसे रखना ये किसे नहीं? आज विश्व में जिनदेशों के पास एवं शस्त्र हैं उनमें सबसे बड़ा जखीरा संयुक्त गण्ड का के पास है। इसके अतिरिक्त रूस, चीन, यूके (ब्रिटेन), इस्टर्न, उत्तर कोरिया, भारत व स्तान जैसे देश भी परमाणु शस्त्र धारक देशों में जाते हैं। बाक़नूद इसके कि ईरान अपी तक यह आया है कि उसके द्वारा किया जा रहा परमाणु उसकी ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने शास्तिपूर्ण कार्यों के लिये है। फिर भी यह क्यों नहीं कि मानवता का सबसे बड़ा हत्यारा देश ईर्ल जो भूखे, निहत्ये बच्चों व बुजुगों औरतों का नरसंहार करता आ रहा, जो अपनी सैन्य शक्ति अमेरिका की शह के बल पर अपने कब्जे की तरफ का लगातार विस्तार करता जा रहा हो जो उसे देने वाले देश फिलिस्तीन के लोगों को ही उनकी ग्रीमि से बेदखल करने की साजिश रच रहा हो, जो इका के इसारे पर पूरे मध्य एशिया में फूट डालने की राजनीति कर रहा हो आखिर थ्रोय संतुलन के लिये उसके सामने ईरान जैसे देश का डटकर होना जरूरी क्यों नहीं?

भारत का विनियोग क्षेत्र में कमज़ोर होना, ये तर्क कांग्रेस का

डॉ. मर्वंक चतुर्वेदी
कमिश ने इन दिनों अपने
युवराज राहुल गांधी के जरिए
लगातार केंद्र सरकार की
आलोचना के लिए जो गस्ता चुना
है, वह सही नजर नहीं आ रहा।
क्योंकि उनके हाथ उठावा गया ये
मुद्दा सत्य से बहुत दूर दिखता है।
उनका तर्क है कि मोबाइल फोन
एवं विनिर्माण क्षेत्र के सभी उत्पाद
भारत में असेंबल किए जा रहे हैं
और उनके पुर्जे विदेश से आयात
किए जा रहे। वे केंद्र सरकार को
यह कहकर घेरते दिखे कि मैंक
इन हँडिया ने फैक्टरी बूम का बादा
किया था। तो फिर विनिर्माण
रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है,
युवा येरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर
क्यों है और चीन से आयात दोगुने
से अधिक क्यों हो गया है? राहुल
यह भी समझते हैं कि इहमें दूसरों
के लिए बाजार बनना बंद करना
होगा। अगर हम यहां निर्माण नहीं
करते हैं, तो हम उन लोगों से
खरीदते रहेंगे जो निर्माण करते हैं।'
किंतु क्या राहुल वहां जो बता रहे
हैं, वह उतना ही सच है, जैसा कि

कहा जा रहा है? भारत क्या विनिर्माण सेक्टर में लगातार कमजोर हुआ है? या फिर जैसा कंग्रेस कह रही है कि हम दूसरों के लिए बाजार बन गए हैं, वह पूरा सच है? चलते हुए जैसा कि अर्थ, वाणिज्य और उद्योग जगत के जानकार जानते हैं, बाजार में हर जंबू भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। प्रति व्यक्ति आव में 67 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार में 135 प्रतिशत, निर्यात में 825 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड स्तर, एफडीआई में 106 प्रतिशत, टैक्सप्रेयर्स की संख्या में 127 प्रतिशत और डायरेक्ट टैक्स संख्या में इजाफ़ा हो रहा है।

इसी जून माह के प्रारंभ में भारत के मैन्युफूरिंग पीएमआई के संबंध में रिपोर्ट देखने को मिली। जो कहती है कि मई में भारत का मैन्युफूरिंग पीएमआई मई में 57.6 रहा। मजबूत मांग और रिकॉर्ड हावरिंग दर्ज की जा रही है।

लाकि मई में पीएमआई अप्रैल 58.2 से मामूली रूप से कम है, फिर भी ध्यान देने योग्य है, पीएमआई 50 से ऊपर होता है यह वृद्धि को दिखाता है। यानी इस वर्तमान में वृद्धि करते हुए

जहां तक विशेष रूप से मोबाइल फोन उत्पादक का विषय है तो इसमें आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पिछले 11 सालों के दौरान 2014 में दो विनिर्माण इकाइयां से बढ़कर आज इनकी संख्या 300 से अधिक हो गई है। मोबाइल फोन का निर्यात 2014-15 में 1,566 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 77 गुना बढ़ि है। यह भी एक तथ्य है कि भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन अब भारत में निर्मित होते हैं, जबकि 2014-15 में यह आंकड़ा मात्र 26 प्रतिशत था। पीएलआई योजना से 10,905 करोड़ रुपये का संचयी निवेश और 7.15 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है। अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई योजना के तहत 1,39,670 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2014 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4.22 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की बढ़ि है, जो निरंतर औद्योगिक और उद्यमशीलता विकास का संकेत है। आप सोचें ये जो नई कंपनियों की संख्या सामने आई है, यह भारत में क्या कर रही है, रोजगार का सृजन, माल का निर्माण और उसकी देशी एवं विदेशी बाजार में उसकी खपत। सरकार ने 1.52 लाख करोड़ रुपये की सेमीकंट्रोलर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है इसलिए कॉम्प्रेस या राहुल गांधी जो आज भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कमजोर होना बता रहे हैं, उनका यह कहना बास्तव में साझ्यों और आंकड़ों के आधार पर सही नहीं है। वह तो देश की जनता को गुमराह करने जैसा है, ताकि बर्तमान सत्ता के प्रति आमजन का विश्वास कमतर किया जा सके।

वह आज के आधुनिक इंट्रास्ट्रॉकर का पारचालक है। पुलवामा व हाल में हुए पहलगाम आतंकी हमले से सभी बाकिफ हैं। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नेहवा झ हवाई बातें नहीं की, बल्कि जो कहा वह करके दिखाया है। देश ने देखा कि किस तरह सेना ने सुस कर मारा। यह तभी संभव होता जब नेतृत्व मजबूत हाथों में हो, और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। मोदी सरकार ने देश की आंतरिक और यात्रा सुरक्षा फोकस करते हुए नक्सलवाद व आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है। पहले देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे जो अब घटकर 18 रह गए हैं। हिंसा में 53 फीसद की कमी आई है। सुरक्षाबलों की हताहत संख्या में 72 फीद गिरावट दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अब नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। संसदीय क्षेत्र सीधी के संदर्भ में: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के म्यारह वर्ष के कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र सीधी में एतिहासिक कार्य हुए हैं। ललितपुर- सिंगरौली रेल परियोजना की आधारशिला 1985 में रखी गई। बाद में परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार होने और स्थानीय स्तर पर मजबूत व पहुंचवाले नेताओं के होने के बावजूद परियोजना को गतिमान बनाने एक धेला भी नहीं दिया गया। रेल परियोजना को गति देने का काम नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद हुआ है। म्यारह वर्ष के प्रवास का नतीजा रहा की रीवा से सीधी और सिंगरौली तक रेल लाइन बिछाने का काम तेज है। जगह झ जगह स्टेशन, पुल आदि का कार्य तेजी से हो रहा है। बघवार तक तो पिछले महीने ट्रायल में रेल आ चुकी है। जिला मुख्यालय में भी शीघ्र बहुप्रतीक्षित रेल पहुंचने वाली है। पिछले 40 वर्ष से ऊपर पड़ी रेल परियोजना को जहाँ मोदी सरकार ने सजीव कर दिखाया वहीं सीधी झ रीवा मार्ग पर कैमोर पहाड़ में विश्वस्तरीय सुरंग का निर्माण कराकर समूचे विंध्य को बड़ी सौगात दी है। सुरंग बन जाने से सीधी और रीवा के बीच आवागमन सुगम व रोमांचित हो गया है। संसदीय क्षेत्र में इसके अलावा बेहतरीन नेशनल हाइवे निर्माणधीन हैं। गांव झ देहत भी सड़क, पेयजल, बिजली की सुविधा से बुक्त हो गए हैं। सीधी झ सिंगरौली में मेडिकल कालेज की स्थापना, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना ने शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। साथ ही सिंचाई परियोजना की शुरूआत आदि ने किसानों को आर्थिक रूप से सुधृद बनाने का काम किया है।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मिला 28 राज्यों के 45 युवा छात्रों का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता से सोमवार को नेशनल गवर्नर्स टूर 2025 पर आए 28 राज्यों के 45 युवा छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू) और अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं।

विधानसभा में शहरी शासन में विधायी पारदर्शिता और जवाबदेही को मुद्रण करना विषय पर आयोजित संवाद में छात्रों ने दिल्ली में विधायी प्रक्रियाओं में जन-धारीदारी और संस्थागत निगरानी को लेकर विभिन्न पहलुओं पर



एविएशन प्यूल की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस की गोदाम ब्रांच की ईर स्टेट सेल (आईएससी) ने एविएशन टरबाइन प्यूल (एटीएफ) की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पदार्थकथा किया है। कर्मवाई के तहत मुंदका स्थित एक गोदाम में 72,000 लीटर एटीएफ जब्त किया गया है, इस तस्करी से सरकार को हर महीने 1.62 करोड़ का नुकसान हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में 6 आयोगियों को गिरफ्तार किया गया है।

इनमें गोदाम मालिक, टैकर ब्रूहर, हेल्पर, ट्रांसपोर्ट और अवैध घूसे से ईंधन खरीदने वाला है। हेल्प कार्टेल को 22 जून को मिली एक सूचना के अधार पर ईंधनबर महिलाएं रिह के नेतृत्व में एसीपी सेमें चंद्र लाला को निगरानी में टीम ने पश्चिमी दिल्ली के मुंदका में एक

चर्चा की। अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने छात्रों को संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया और उन्हें ईमानदारी तथा सेवा धाराना से जननवाप्ति प्रश्नों का उत्तर दिया। गुप्ता ने कहा कि वह विधानसभा जनता

की है। आपकी सक्रिय धारीदारी और निजस्व दृष्टिकोण भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की शक्ति का प्रतीक है।

दिल्ली विधानसभा में विभिन्न सुधारात्मक कार्य चल रहे हैं। हाल ही में विधानसभा जनता

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने 3,400 गज्जों की मरम्मत का किया

नई दिल्ली, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को 3400 गज्जों को भरकर 1,400 किलोमीटर से अधिक सड़कों को सुविधा, सुगम और मानसुन के लिए तैयार करने का एलान किया है। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह नहीं है कि पिछले चार महीने से कुछ नहीं हो रहा था। गहरे भरने का काम लगातार चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि मानसुन कभी भी दस्तक दे सकता है, इसलिए हमने तय किया है कि एक ही दिन में 3,400 चिनित गज्जों को भर दिया जाएगा। ये सिर्फ़ एक मरम्मत नहीं, जनता से किया गया वादा निभाने का दिन होगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक स्थायी और पारदर्शी प्राणी को मुकुर अतृ त है।

उन्होंने कहा कि जब काम जिना प्राचारकर के होगा, तो गहरे बर्नेंगे ही नहीं। जब काम पीड़ब्ल्यूडी के



तब मापदंडों के अनुसार होगा, तब सड़कों पर जनता को तकलीफ नहीं होगी। वही हमारा संकल्प है। अधियाय की विशेषताएँ : 1,400 किलोमीटर पीड़ब्ल्यूडी सड़कों का कार्यक्रम होगा। इनमें मेन रोड, अंतरिक सड़कों और हाई रोड के लिए एक जोन में एविएशन

प्रशिक्षण का नियमित विद्युत

